

विश्व सदमे में है, पहले अमेरिका द्वारा लगाये गये टैरिफ से और फिर टैरिफ प्रक्रिया को अचानक आगे खिसकाने से

इस घटनाक्रम ने ट्रम्प की नीतियों की अनिश्चितता व अव्यवहारिकता पर से पर्दा हटा दिया

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। ट्रंप के टैरिफ ने जब पूरी दुनिया और वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है और ट्रंप ने इस नीति के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर नेताओं से लेकर बाजार तक सभी को चौंका दिया है।

अब उतनी ही जल्दबाजी में उन्होंने रैसप्रोकल टैरिफ का टाइम आगे खिसका दिया। उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया, जिससे बाजारों में थोड़ा उछाल आया। उन्होंने चीन को छोड़कर सभी देशों को टैरिफ में राहत दी।

इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप प्रशासन की पूर्णतया अप्रत्याशित तथा अवास्तविक कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। उनके करीबी अधिकारियों, जिसमें अमेरिका के वाणिज्य सचिव भी शामिल हैं, को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। ट्रंप प्रशासन की अनिश्चितता ने एक बार फिर बाजार को प्रभावित किया और बाजार का उछाल थम गया।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी बहुचर्चित टैरिफ नीति को उन्होंने रोक दिया, क्योंकि यह साफ तौर पर पीछे हटना ही है।

■ पर, ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका के ट्रेंजरी सैक्रेटरी स्कॉट बैसैंट ने ट्रम्प के निजी निवास पर जाकर, अमेरिका के “बॉण्ड मार्केट” की स्थिति से उन्हें अवगत कराया।

■ जैसा कि विदित ही हैं, कोई भी सरकार अपने पुराने ऋण नहीं चुकाती, केवल नये ऋण लेकर, पुराने ऋण की प्रतीकात्मक अदायगी करती हैं। पर, अगर, सरकार के बॉण्ड्स मार्केट में ढीले पड़ जायें तो बाज़ार से नया ऋण उठाने का क्रम टूट सकता है।

■ शायद स्कॉट बैसैंट ने यह स्थिति ट्रम्प के सामने उजागर की और इससे मंदी का दौर (डिप्रेशन) शुरू होने की आशंका जताई।

■ 1930 के “ग्रेट डिप्रेशन” के दृश्यों को अमेरिका भूला नहीं है और “डिप्रेशन” बड़ा भयानक शब्द है अमेरिका वासियों के लिये।

■ बैसैंट के संदेश व निष्कर्ष को अमेरिका के जाने-माने उद्योगपतियों व इकॉनमिस्टों ने ट्रम्प को सीधे लगातार फोन कर दोहराया और अन्त में ट्रम्प को अपने टैरिफ लगाने के प्लान को 90 दिन स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा।

ट्रंप ने जोर-शोर से दावा किया था कि उनकी ट्रेड वॉर नीति में कोई बदलाव

नहीं होगा। वे इस नीति को अवश्य ही लागू करेंगे। उन्होंने यह भी डींग मारी थी

कि 75 से अधिक देशों ने उनसे विनती की है कि वे कोई समझौता करें और उनके बड़े हुए टैरिफ से राहत दें।

उन्होंने हमेशा की तरह टैरिफ उपायों को लेकर शेखी बघारी। लेकिन, उनके आंतरिक सर्कल में सभी देशों पर एक साथ इतने कठोर उपाय लागू करने का आत्मविश्वास और भावना अब धीमी होती जा रही थी और अधिक व्यावहारिक सोच सामने आ रही थी।

रिपोटर्स के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, ट्रंप के निजी निवास पर पहुँचे, ताकि बाज़ार की स्थिति को लेकर उन्हें आगाह कर सकें। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट में भारी गिरावट आई है और यही वह धुरी है, जिस पर संघीय सरकार की वित्तीय स्थिति घूमती है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (सोएनएन) ने रिपोर्ट किया कि बुधवार को अमेरिकी संघीय सरकार के बॉन्ड ऑफर को वह प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो सामान्यतः मिलती है।

टैरिफ से उत्पन्न उथल-पुथल के बाद, अमेरिका का सरकारी ऋण खरीदने वाले बड़े निवेशकों में अब उतना उत्साह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बाल आयोग अध्यक्ष का कार्यभार आईएस को क्यों सौंपा’

जयपुर, 10 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार आईएस अधिकारी को सौंपने पर मुख्य सचिव, संयुक्त बाल अधिकारिता सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और आईएसएस कुलदीप रांका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने

■ हाई कोर्ट ने आयोग की सदस्य संगीता गर्ग की याचिका पर नोटिस जारी किये।

यह आदेश आयोग की सदस्य संगीता गर्ग की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चंदोलिया ने बताया कि संगीता बेनीवाल द्वारा इस्तियाफ देने के कारण आयोग अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गत 5 फरवरी को आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप रांका को सौंप दिया। याचिका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गृह मंत्री चेन्नई पहुँचे

उनकी यात्रा का मुख्य मकसद तमिलनाडु के नये प्रदेशाध्यक्ष का चयन है

-लक्ष्मण वैकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। तमिलनाडु भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, राज्य में इस पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। अब भाजपा की तमिलनाडु इकाई के इस सर्वोच्च पद पर कोई नया व्यक्ति ही आयेगा।

गुरुवार को भाजपा की राज्य एवं चेन्नई इकाईयाँ सक्रिय घटनाक्रम की साक्षी रहीं। दरअसल, केन्द्रीय गृहमंत्री तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राज्य के दौरे पर यहाँ आये थे। उन्होंने राज्य की राजनैतिक स्थिति का आकलन करने के लिये दिन पर राज्य के विभिन्न पार्टी नेताओं के साथ कई मीटिंग कीं। उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल सभी उम्मीदवारों से मुलाकात की।

पार्टी के इस अन्दरूनी मामले के अलावा, ऐसी आशा की जा रही है कि अमित शाह अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करने के सिलसिले में भी बात

■ अमित शाह ने दिन भर प्रदेश के भाजपा नेताओं से विचार-विमर्श किया, जिसका लक्ष्य राजनीतिक रणनीति तय करना था, अगले वर्ष तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिये।

■ इसी क्रम में अमित शाह, अन्नाद्रमुक से चुनावी गठबंधन की योजना को संभवतः स्वीकृति भी देंगे।

■ जैसा कि विदित ही है, तमिलनाडु में भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन टूट गया था, प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहने से। अन्नामलाई ने स्वर्गीय जयललिता को भी नहीं बख्शा था।

■ दोबारा गठबंधन करने के लिए अन्नाद्रमुक की शर्त थी कि अन्नामलाई की जगह किसी नये व्यक्ति को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाये।

करेंगे। ज्ञातव्य है कि अन्नाद्रमुक लोकसभा चुनावों से ठीक पहले गठबंधन से अलग हो गई थी, क्योंकि अन्नामलाई ने जयललिता सहित, अन्नाद्रमुक के शीर्षस्थ नेताओं पर निशाना साधते हुये, पार्टी की तीखी

आलोचना की थी।

यद्यपि अन्नाद्रमुक ने फिर से गठजोड़ करने की इच्छा के संकेत दिये हैं, लेकिन समझा जाता है कि गठबंधन के लिये उसकी पूर्व शर्तों में से एक शर्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने बांग्लादेश के ट्रक रोके

ढाका/नयी दिल्ली, 10 अप्रैल। भारत ने पश्चिम बंगाल सीमा से सटे बेनापोल लैंड पोर्ट चेक पोस्ट के रास्ते माल के साथ आ रहे बांग्लादेश के चार ट्रकों को वापस भेज दिया है। यह कार्रवाई बांग्लादेश को दूसरे देश में माल भेजने के लिए दी गयी ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द किये जाने के एक दिन बाद

■ ट्रांजिट सुविधा वापस लेने का आदेश जारी होने के आगले दिन यह कार्यवाही की गई।

की गयी है। बांग्लादेश के टीवी समाचार चैनल बीडी न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के जेसोर जिले में बेनापोल पोर्ट के उप निदेशक रशीदुल साजिब नजीर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मंगलवार को ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने के कारण पैदापोल कस्टम्स (भारतीय पक्ष) ने तीसरे देश के माल को अपने सीमा से ले जाने की मंजूरी देने से इन्कार कर दिया।

राहुल गांधी ने रणथम्भौर में टाइगर देखे

सवाई माधोपुर, 10 अप्रैल (निस) । लोकसभा विपक्ष के नेता व कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर रणथम्भौर आए हुए हैं। उन्होंने आज सुबह और शाम की पारी में रणथम्भौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी कर बाघों की अठखेलियां देखीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से बुधवार को सीधे अहमदाबाद से फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। जयपुर से सड़क मार्ग से देर रात करीब 10 बजे सवाई माधोपुर के रणथम्भौर पहुंचे। राहुल यहां रणथम्भौर के शेर बाग होटल में ठहरे हुए हैं।

राहुल गांधी ने पांच सितारा होटल

■ राहुल ने सुबह और शाम दोनों पारी में जंगल का भ्रमण किया।

शेरबाग में रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह और शाम की पारी में उन्होंने रणथम्भौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अठखेलियां देखीं। इस दौरान राहुल गांधी ने बाघिन टी 84 एरोहेड व उसके शावकों की अठखेलियों को अपने कैमरे में भी कैद किया।

राहुल ने रणथंभौर के जोन नंबर दो में फिमेल टाइगर के दीदार किए। बाघिन व शावकों की अठखेलियां देख कर राहुल गांधी खुश हो गए। उल्लेखनीय है कि गांधी परिवार का रणथम्भौर से गहरा लगाव है। राहुल गांधी की बहन और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा भी अक्सर रणथम्भौर आती रहती हैं।

क्या टैरिफ वॉर के कारण भारत को मजबूरन द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक रिफॉर्म लागू करने पड़ेंगे?

टैरिफ वॉर के कारण अमेरिका का मार्केट शायद भारत के उद्योगपतियों की पहुँच से बाहर हो जायेगा तथा भारत को विश्व में अन्यत्र मार्केट विकसित करने होंगे

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। माना जा रहा है कि अमेरिका की नई टैरिफ नीति, विशेष रूप से रैसप्रोकल टैरिफ की 5 अप्रैल की घोषणा से भारत में सैकण्ड -जनरेशन रिफॉर्म्स (सुधारों) की शुरुआत हो सकती है। सुधारों की पहली बड़ी लहर तीन दशक पहले 1991 में आई थी। टैरिफ और ट्रेड पॉलिसीज से अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रणनीतियों में बदलाव आता है, और भारत के सामने, इस तरह के ग्लोबल परिवर्तन को प्रतिक्रिया में सुधारों को तेजी से बढ़ाने का अनोखा मौका है।

चूँकि, अमेरिकी टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है, इसलिए भारत अपने घरेलू बाजार पर अधिक फोकस करने और अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इस परिदृश्य में भारत की सरकार, व्यापार करने की सुविधा को बढ़ाने,

■ इस नए मार्केट में सफल होने के लिए भारत को सैकण्ड जनरेशन रिफॉर्म्स लागू करने पड़ेंगे, जैसे, लेबर लॉज में लचीलापन, कृषि उत्पाद की श्रृंखला को मजबूत करना और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को और मजबूत करना। जब तक यह नहीं करेंगे, भारतीय माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जम नहीं पाएगा।

■ ये रिफॉर्म्स शायद कालांतर में धीरे-धीरे भारत में आते, पर, टैरिफ वॉर से उत्पन्न स्थिति ने शायद भारत सरकार से धीरे-धीरे “सैकण्ड जनरेशन रिफॉर्म्स” लागू करने का विकल्प छीन लिया है, अब, तुरंत ही ये परिवर्तन करने होंगे।

■ जैसा कि विदित ही है, “फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स” 1991 में, लगभग तीन दशक पहले लागू हुए थे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने और व्यवसायों के लिए रेगुलेटरी बोझ को कम करने की दृष्टि से सैकण्ड जनरेशन (दूसरी पीढ़ी के) सुधारों को आगे बढ़ा सकती है। ये प्रयास भारतीय कंपनियों

को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे और विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम करेंगे। अमेरिका में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज (संरक्षणवादी नीतियों) के

को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे और विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम करेंगे। अमेरिका में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज (संरक्षणवादी नीतियों) के

बढ़ने से भारत अपने पारंपरिक पार्टनरों के अलावा और अन्य लोगों से ट्रेड पार्टनशिप कर सकता है। यदि अमेरिकी बाजारों पर निर्भरता अधिक घटती हो जाती है तो भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को आगे बढ़ा सकती है। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए और 238 से अधिक घायल हुए।

बदलते ग्लोबल ट्रेड परिदृश्य के जवाब में भारत, इलैक्ट्रॉनिक्स, इस्पात और दवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को भी तेज कर सकता है।

इतना ही नहीं, भारत सरकार श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण और टैक्सेशन में गहन सुधारों को आगे बढ़ा सकती है, ताकि भारतीय निर्यात क्षेत्र को अधिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लाल किले और जामा मस्जिद पर बम की धमकी

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल, दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले और जामा मस्जिद को निशाना बनाकर बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी। इसके बाद

■ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुछ नहीं मिला। धमकी फर्जी साबित हुई।

सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ही मौके पर पहुंच कर गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, जांच में कुछ भी नहीं मिला और ये धमकी फर्जी साबित हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने थो। अमेरिका की सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण सबूत दिए, जो दिसम्बर 2011 में प्रस्तुत एन.आई.ए. की चार्जशीट का अंग बन गए। यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायत समिति की मांग को लेकर राजसमंद का कुंवारिया कस्बा दूसरे दिन भी बंद रहा

तहसील कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा

राजसमन्द, (निसं)। जिले में कुंवारिया कस्बे को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी ग्रामीणों और व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह बंद रखे और तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों में स्थानीय व्यापारी, समाजसेवी, युवा और महिला संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा ग्रामीण शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार सुबह से ही तहसील कार्यालय परिसर में लोग बारी-बारी से धरने पर बैठते रहे और आंदोलन की अगली रणनीति तैयार करते रहे। व्यापारियों ने पूर्ण बाजार बंद रखकर समर्थन जताया। आवश्यक सेवाओं को भी सीमित समय के लिए खोला गया। कुंवारिया बाजार के पूरी तरह बंद रहने से आस-पास के गांवों से आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खरीदारी के लिए आए लोगों को न दवा की दुकानें मिलीं और न ही दैनिक उपयोग की वस्तुएं। शुक्रवार को भाजपा से पंचायत समिति सदस्य कुसुम तातेड़ सहित 1100 भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी की



कुंवारिया कस्बे को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर बाजार बंद रहा।

जा रही है। कुंवारियां के हक की लड़ाई में सहयोग देते हुए गुरुवार को दूसरे दिन भी बंद का समर्थन किया। पंचायत समिति की मांग को लेकर व्यापारियों व आमजन ने किस प्रकार से कुंवारिया बंद का समर्थन किया उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुंवारिया में चाय की थड़ी, पान की

दुकान से लेकर बड़े व्यापार प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे पूर्व प्रधान भानू पालीवाल ने भी कुंवारिया के आमजन की मांग का समर्थन करते हुए मांग को जायज बताया। उन्होंने कहा कि दो दशक से स्थानीय लोगों की चली आ रही मांग को पूरा करना

चाहिए। क्योंकि पंचायत समिति बनने के लिए तय मापदण्ड कुंवारिया कस्बे में उपलब्ध होने के बाद भी नंजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुंवारिया पंचायत समिति बनेगी तो क्षेत्र के काश्तकारों, ग्रामीणों व आमजन को काफी राहत मिलेगी। भाजपा मीरा मण्डल के

■ **भाजपा से पंचायत समिति सदस्य कुसुम तातेड़ सहित 1100 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी की जा रही है**

प्रतिनिधि सदस्य कालुसिंह राठौड़ ने भी ग्रामीणों की वाजिब मांग का समर्थन किया।

धरना प्रदर्शन में कुंवारिया प्रशासक ललित श्रीमाली, उपसरपंच सुरेश जाट, फियावडी प्रशासक सुरेशचन्द्र चौधरी, पंसस कुसुम तातेड़, विजय गुर्जर, घाटी उपसरपंच विजय प्रकाश सनाद्वय, सर्व व्यापार मण्डल अध्यक्ष गिरिराज मूंदड़ा, महामंत्री यशवंत पीपाड़ा, पूर्व सरपंच दोलत सिंह शकतावत, पूर्व पंसस मुकेश शर्मा, कालूराम जाट, डालचंद कुमावत, पूर्व उपसरपंच रमेश कीर, गोवर्धनदास वैष्णव, बद्रीलाल कीर आदि सहित दर्जनों लोगों ने विचार व्यक्त किए।

प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के गिरोह का पर्दाफाश



पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की सफ़्टाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया।

जमवारामगढ़, (निसं)। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की सफ़्टाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप यादव और वृत्ताधिकारी जमवारामगढ़ के सुपरविजन में यह कार्रवाई थाना जमवारामगढ़ पुलिस

द्वारा अंजाम दी गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एसएमएस अस्पताल के दवा वितरण केंद्र का सविदाकर्मी और न्यू शर्मा मेडिकल स्टोर (एसएमएस अस्पताल के पास) का संचालक भी शामिल है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रंज अजयपाल लांबा के निदेशन में चलाए जा रहे

“ऑपरेशन क्लीन स्वीच” और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रजनीश पुनिया के नेतृत्व में “ऑपरेशन नॉकआउट” के तहत की गई। संयुक्त टीम डीएसटी जयपुर ग्रामीण और थाना आंधी पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया, जो नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में सक्रिय था।

नकली सोने को असली बताकर गोल्ड लोन लिया

बीकानेर, (निसं)। नकली सोने को असली बताकर लाखों रुपए का गोल्ड लोन लेने का मामला सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में नौ लोगों के खिलाफ जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कराया है। पिछले दिनों बैंक की ऑडिट के दौरान ये मामला सामने आया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खतुरिया कॉलोनी शाखा के प्रबंधक धीरज खंडेलवाल ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आठ लोगों पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में कहा गया है कि नौ ग्राहकों और तीन स्वर्णकारों ने मिलकर बैंक से लाखों रुपए का लोन उठाया है। बैंक ने सोने के असली होने की रिपोर्ट के आधार पर लोन दे दिया। पिछले दिनों

एक ऑडिट टीम ने बैंक में इस गोल्ड को जांचा परखा, तो ये नकली पाया गया। दरअसल, जिन ग्राहने के आधार पर लोन दिया गया था, उनमें सोना बहुत कम था, जबकि नकली हिस्सा ज्यादा था। खंडेलवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने चेतन, हेमंत कुमार, प्रकाशनिर्मल, राधा देवी, रमजान, सदाकत अली, सीताराम, सुरजाराम और यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

इसी मामले में बारह जनों पर फर्जीबाड़ा करने का आरोप है। पुलिस उन स्वर्णकारों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने नकली सोने को असली बताते हुए लोन दिलाने में सहायता की थी। ये पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी एफबीआई ने ही फर्जी रिपोर्ट का खुलासा किया था।

जेवर व नकदी चोरी उदयपुर। शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में सूते मकान से चोर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ले गए।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरनगर पुर्बिया कॉलोनी मल्लातलाई अम्बामाता निवासी अर्जुनलाल कुमावत पुत्र शंकरलाल के सूते मकान से चोर सोने की 2 अंगुठियां, इयरिंग, चांदी की पायल, बिछियां, अंगूठी तथा 15 हजार की नकदी चुरा ले गए। रात में मकान की छत के रास्ते नीचे उतर कर चोर वारदात कर फरार हो गए। पीड़ित के घर लौटने पर ताला टूटा व सामान कमरों में सामान बिखरा मिलने पर प्रकरण दर्ज करवाया। वहीं खेरोदा कस्बे के रोही खेड़ा गांव में स्थित तीन मकानों से नकबजनी कर चोर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ले गए। 9 अप्रैल रात में आए तोलीराम पुत्र निहाराम के मकान की छिड़की खोल अंदर घुसे चोर जेवर व नकदी चुरा ले गए।

चरागाह भूमि से अवैध कोयला भट्टियां हटाई

उदयपुर, (निसं)। नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लगी गई अवैध कोयला भट्टियों को प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने ध्वस्त कर दिया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी छेल कुंवर ने बताया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को शिकायत प्राप्त होने पर मावली उपखण्ड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया के लकड़ी को सुरक्षित रख दी गई। मौके पर कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आस पड़ोस के लोगों को उक्त नगर पालिका सम्पत्ति को खुद बुर्द नहीं करने बाबत व अन्य उपयोग में नहीं लेने बाबत पांबंद किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर एक

किया। नगर पालिका से कनिष्ठ अभियन्ता भगवती लाल खारीवाल, सीनीयर ड्राफ्ट मैन हेमन्त मालवीया एवं कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक भगवत सिंह आदि भी मौजूद रहे। टीम ने संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की। साथ ही संबंधित स्थान पर पालिका सम्पत्ति के दो बोर्ड लगवाये। जले हुए कोयलों की सुरक्षित रखा गया एवं अग्निशमन वाहन से चारों तरफ पानी का छिड़काव कर लकड़ी को सुरक्षित रख दी गई। मौके पर कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आस पड़ोस के लोगों को उक्त नगर पालिका सम्पत्ति को खुद बुर्द नहीं करने बाबत व अन्य उपयोग में नहीं लेने बाबत पांबंद किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर एक

■ **आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है**

की आशंका खुद मौसम विभाग ने जताई है। बीकानेर के निवासियों को मौसम विभाग ने बाकायदा एसएमएस करके अलर्ट दिया है कि गर्मी में बढ़ गई है। लू चलने की आशंका है। बीकानेर के अलावा भी कई जिलों में ऐसे ही अलर्ट एसएमएस के माध्यम से दिए गए हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने लू और तापघात के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा कार्य स्थलों पर छाया, पानी और दवाइयों की

पर्याप्त व्यवस्था रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए पानी की खिलियां भरवाने तथा पक्षियों के लिए परिड़े लगाने का अभियान चलाने को कहा। जिला कलेक्टर ने कहा कि पशुपालन विभाग के अधिकारी सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गौशालाओं में पेयजल छाया और चारे की कोई कमी नहीं हो। उन्होंने मोबाइल वेटेरनरी वैन के टोल फ्री नंबर 1962 को प्रचारित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रियों की सघन चेकिंग करते हुए बर्फ बनाने में काम लिए जाने वाले पानी के नमूने लेने के लिए दिए गए। वहीं कहा कि कैपर से सफ़ाई होने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जाए। रोडवेज बस स्टैंड पर छाया पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

सैलून संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। जवाहर नगर थाना इलाके में एक सैलून संचालक ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता उस समय चला जब युवक के घर नहीं पहुंचने पर उसके परिवार वाले उसको ढूँढते हुए दुकान पर पहुंचे, जहां युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसे नीचे उतार कर उपचार के लिये कोटा के निजी चिकित्सालय ले गये, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

जवाहर नगर थाने के एसएसआई किशोरीलाल ने बताया कि मृतक केसुआ निवासी मनीष (35) है जिसकी तलवंडी इलाके में सैलून की दुकान है। एसएसआई ने बताया कि युवक दुकान से शाम को सात बजे तक घर पर

■ **आत्महत्या के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया है, मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है**

लौट जाता था लेकिन बुधवार रात्रि तक घर पर नहीं आने पर परिजन उसे ढूँढते हुए दुकान पर पहुंचे जहां युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। एसएसआई ने बताया कि गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आत्महत्या के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया है। मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

बढ़ती महंगाई का विरोध, आनासागर झील में फेंके गैस सिलेंडर

अजमेर, (कासं)। देश सहित प्रदेश में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आनासागर झील में गैस सिलेंडर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आम जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।

यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वैशाली नगर रीजनल कॉलेज वाली चौपाटी पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मल्होत्रा ने बताया कि केंद्र में भाजपा की सरकार को साल वर्ष पूरे हो चुके हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री बड़े-बड़े वादे करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है।

वर्तमान में गैस के सिलेंडर हजार रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी



आनासागर झील के किनारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य में चुनाव आने पर गैस सिलेंडर के

दाम कम कर दिए जाते हैं। जनता को पागल बनाने और भ्रमित करने का काम

भाजपा सरकार कर रही है। चुनाव आने के बाद किसी न किसी बहाने से भाव बढ़ा

■ **कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आम जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया**

दिए जाते हैं।

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज वैशाली नगर रीजनल कॉलेज चौपाटी के पास आनासागर झील में गैस सिलेंडर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं पदाधिकारियों का कहना रहा कि आए दिन गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मध्यम वर्ग दाम बढ़ने से परेशान हो चुका है। रसोई का बजट बिगड़ चुका है। यूथ कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार से मांग करती है कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल के दाम कर मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करें। अन्यथा यूथ कांग्रेस द्वारा जनआंदोलन किया जाएगा।



भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड



केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना सं. 01/2025 सहायक लोको पायलट (एएलपी) की भर्ती

सांकेतिक सूचना

नीचे तालिका में दिये गये अनुसार सहायक लोको पायलट के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा किये जाने चाहिए।

आवेदन खुलने की तिथि: 12 अप्रैल 2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 11 मई 2025 (23:59 बजे)

पद का नाम	7 ^{वें} सीपीसी के अनुसार वेतन लेवल	प्रारंभिक वेतन (₹)	शैक्षणिक एवं चिकित्सा मानक	1.7.2025 को आयु	कुल रिक्तियां (सीसी आरआरबी)
सहायक लोको पायलट (एएलपी)	2	19,900 /-	विस्तृत सीईएन का संलग्नक-ए	18-30 वर्ष	9970

उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें ताकि गैर-आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्मतिथि को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्मतिथि के साथ 100 प्रतिशत मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनीकृत फोटो और नवीनीकृत बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिड) के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।

यह अधिसूचना पूर्ण रूप से सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन सं. 01 / 2025 (एएलपी) को मूल्य-मात्रित करने की सलाह दी जाती है। उपरोक्त भर्ती के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट / महत्वपूर्ण सूचना समय-समय पर नीचे वर्णित आरआरबी की वेबसाइटों पर जारी की जाएगी।

सीईएन सं. 01/2025 में प्रतिभागी आरआरबी की वेबसाइट

अहमदाबाद www.rbahmedabad.gov.in	अजमेर www.rbbajmer.gov.in	गोपाल www.rbbhopal.gov.in	गुन्नेस्वर www.rbbbsa.gov.in
बिलासपुर www.rbbilaspur.gov.in	चंडीगढ़ www.rbbcdg.gov.in	चेन्नई www.rbbchennai.gov.in	गुवाहाटी www.rbbguwahati.gov.in
जम्मू श्रीनगर www.rbbjammu.nic.in	कोलकाता www.rbbkolka.gov.in	मालदा www.rbbmalda.gov.in	मुंबई www.rbbmumbai.gov.in
गुजफरपुर www.rbbmuzaffarpur.gov.in	पटना www.rbbpatna.gov.in	प्रयागराज www.rbbprg.gov.in	रांची www.rbbbranchi.gov.in
शिकन्दराबाद www.rbbsecunderabad.gov.in	शिलिगुरी www.rbbshiliguri.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rbbthiruvananthapuram.gov.in	गोरखपुर www.rbbgkp.gov.in

रैमबो / अज. / एडीसीटी / 01 / 2025

दिनांक: 11.04.2025

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड

दलालों, बिचौलियों और नौकरी का झोसा देने वालों से सावधान रहें।

‘जनता पानी के लिये परेशान हुई तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने बढ़ती गर्मी में पेयजल सप्लाई की मैराथन बैठक ली

जयपुर, 10 अप्रेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद, पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में आमजन को बढ़ी हुई मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलैक्टर कन्टिन्जेंसी प्लान के अनुसार पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किसी तरह की किल्लत नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को भी पेयजल की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी में पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गर्मी में जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो जिम्मेदारों की खैर नहीं।

■ सभी कलैक्टरों को कन्टिन्जेंसी प्लान के अनुसार, पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करने व शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत नहीं होने देने के निर्देश दिये।

में पीएचईडी के फील्ड अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए नए हैण्डपम्प, नलकूप लगाने, पुराने हैण्डपम्प, नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरुस्त करने सहित, पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिला कलैक्टरों को एक-एक करोड़ रुपए

का अनटाइड फंड उपलब्ध करवाया गया है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीएचईडी) भास्कर ए. सावंत ने बताया कि विभाग की वृहद् परियोजनाओं में कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से इनके कार्य करवाए जा रहे हैं।

‘बाल आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कहा गया कि आयोग अध्यक्ष का कार्यभार किसी आईएसएस अधिकारी को देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। विभाग की साल 2010 की अधिसूचना के तहत यदि अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उसका कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आईएसएस कुलदीप रांका को बिना किसी प्रावधान अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयोग की वरिष्ठ सदस्य हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाजशीट राणा सहित 9 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई थी। स्पेशल एनआइए कोर्ट ने दिल्ली में गैर जमानती वॉरंट जारी किए और इंटरपोल से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद मांगी गई।

पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि यह सारी कवायद शांति से हो रही कानूनी कूटनीति थी न कि मीडिया स्टंट। वर्ष 2012 में विदेश मंत्री सलमान खुशींद और विदेश सचिव रंजन मथाई ने अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन व अंडर सैक्रेटरी वैंडी शरमन के समक्ष तहखुराणा और हेडली का मुद्दा उठाया। जनवरी 2013 में हेडली को 35 साल की जेल हो गई और राणा को पहले ही जेल हो चुकी थी। भारत ने जोरदार तरीके से हेडली के प्रत्यर्पण की मांग उठाई। यूपीए सरकार ने उसकी सजा पर निराशा जताई।

अमेरिका में भारत की राजदूत निरुपमा राव लगातार यह मुद्दा उठाती रहीं। वर्ष 2015 में हेडली 26/11 केस में गवाह बन गया। वर्ष 2016 में मुम्बई कोर्ट ने उसे पूर्ण सहयोग की शर्त पर माफी दे दी, जिससे जैवद्वीन अंसारी (अबु जुंडाल) के खिलाफ केस तैयार करने में मदद मिली।

दिसम्बर 2018 में, कानूनी बाधाओं के

समाधान के लिये, एक टीम अमेरिका गई थी तथा जनवरी 2019 में एक बार फिर कहा गया था कि राणाको अपनी पूरी सजा अमेरिका में ही काटनी होगी। सजा में गुजरे समय को ध्यान में रखते हुये, उसकी रिहाई 2023 में तय हुई थी। ये “स्ट्रूंग लीडर” क्षण नहीं, बल्कि न्याय के मंद गति से चलने वाले पहिये हैं, जो सालों की मेहनत से आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरम को यह बात समझाने में काफी कष्ट उठाना पड़ा।

उन्होंने कहा, जून 2020 में, स्वास्थ्य कारणों से हुई राणा की रिहाई के बाद, भारत सरकार ने उसकी गिरफ्तारी का आग्रह किया। बाइडन सरकार ने उसके प्रत्यर्पण का समर्थन किया। मई, 2023 में, अमेरिकन अदालत ने “अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण समझौते” के तहत, उसका प्रत्यर्पण प्रमाणित कर दिया। राणा ने अपील की और कई याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी शामिल थी, और अंत में, दोहरी जोखिम का हवाला देते हुये, एक रिट याचिका अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में लागाई। उसकी सारी याचिकाएँ खारिज कर दी गई। अंतिम इनकार, डॉनल्ड ट्रम्प के शपथ-ग्रहण समारोह के एक दिन बाद, 21 जनवरी, 2025 को किया गया।

फरवरी 2005 में, प्रधानमंत्री मोदी तथा

राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में एक साथ खड़े होकर, उस चीज का श्रेय लेने की कोशिश की, जो मूलतः यूपीए काल के कई सालों के ग्राउन्ड वर्क का परिणाम था। भारतीय अधिकारियों ने 17 फरवरी तक 26/11 के षडयंत्र में राणा की भूमिका की पुष्टि कर दी थी। यह पुष्टि काफी पहले, 2005 में ही कर दी गई थी। जब वह एलईटी तथा आईएसआई के सदस्यों के बीच समन्वय का कार्य कर रहा था। अन्त में, 8 अप्रैल 2025 को, अमेरिकन अधिकारियों ने राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। वह 10 अप्रैल को नई दिल्ली आ गया। तथ्य स्पष्ट होने ही चाहिये- मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की पहल नहीं की, न ही इसने कोई नया ब्रेक थ्रू ही किया। इसने तो केवल यूपीए-काल में शुरू की गई परिपक्व, सतत एवं रणनीतिक कूटनीति का लाभ लिया। यह प्रत्यर्पण किसी “ग्राउन्ड स्टैन्डिंग” का परिणाम नहीं है। यह तो एक ऐसा विधान है, जिसे भारत सरकार प्राप्त कर सकती है, जब कूटनीति, विधि-प्रवर्तन (लॉ एन्फोर्समेंट) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में पूरी नेकनीयती से आगे बढ़ा जाता है तथा इसमें अपनी पीठ थपथपाने जैसे कोई चीज नहीं होती। तथ्यों को आम जनता तक पहुँचाते हुये, यह बयान समाप्त हुआ।

क्या टैरिफ वॉर के कारण भारत को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, जो कि “मेक इन इण्डिया” पहल के अनुरूप होगा।

वैश्विक व्यापार में हो रहे बदलाव कृषि और श्रम कानूनों में भी सुधार को गति दे सकते हैं, जिन्हें भारत में अक्सर द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के रूप में देखा जाता है। इन क्षेत्रों में नए दबावों से निपटने के लिए, भारत लचीले श्रम कानूनों और कृषि आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार ला सकता है, जिससे किसानों को वैश्विक बाजारों से बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर मिले और अक्षम व्यवस्थाओं को कम किया जा सके।

ट्रेड का बदलता परिदृश्य भारत को डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन (नवाचार) पर भी ध्यान केन्द्रित करने को प्रेरित कर सकता है।

इस क्षेत्र में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, ई-कॉमर्स रैगुलेशन्स को सरल करना और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (ए.आई.) तथा ऑटोमेशन में निवेश आदि शामिल हो सकते हैं। इससे भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल सेंटर के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी, विशेषकर, यदि पारंपरिक निर्माण उद्योग

अमेरिका में अधिक टैरिफ का सामना करते हैं।

इसके अलावा, भारत शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार करके मानव संसाधन को भी मजबूत बना सकता है। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टैम (साइन्स, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग एण्ड मैथमैटिक्स) शिक्षा में निवेश, और वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने वाली नीतियाँ शामिल हो सकती हैं। ये सुधार टेक्नॉलजी और हरित ऊर्जा जैसे उभरते उद्योगों में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिला सकते हैं।

नई टैरिफ नीति भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है, और इसके जवाब में भारत विदेशी निवेश और टेक्नॉलजी ट्रांसफर को आकर्षित करने वाले सुधार लागू कर सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाधाओं को दूर करके और निवेश-अनुकूल वातावरण बनाकर, भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रह सकता है।

तथापि, भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत अपने उद्योगों को सशक्त बनाना

चाहता है, उसे एक ऐसे वैश्विक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहना होगा, जहाँ “ट्रेडिशनल ट्रेड पैटर्न” बदल रहे हैं। इसके अलावा, द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की गति को राजनीतिक और नौकरशाही शक्तियों से भी विरोध झेलना पड़ सकता है, विशेषकर कृषि, श्रम और भूमि सुधारों जैसे क्षेत्रों में। अमेरिका की शूलक नीति से उत्पन्न व्यापक वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी भारत के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, जिससे सावधानी से निपटना होगा।

इस प्रकार, अमेरिका की नई शूलक नीति भारत को द्वितीय पीढ़ी के सुधारों को तेज करने के लिए प्रेरित कर सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जो घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लाने में सहायक हो सकती है। भारत की प्रतिक्रिया रणनीतिक सुधारों का एक मिश्रण हो सकती है, जैसे निर्माण, कृषि, श्रम कानून और व्यापार नीतियाँ, जो वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के प्रति अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बना देंगी। ये सुधार भारत के, 21 वीं सदी में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के, दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप होंगे।

गृह मंत्री चेन्नई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह थी कि अन्नामलाई के साथ काम करना उसके लिये मुश्किल होगा तथा वह राज्य भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अन्नामलाई के अलावा, किसी अन्य नेता के साथ डील करना पसंद करेगी।

चूँकि अब अन्नामलाई अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, इस महत्वपूर्ण पद के लिये अन्य नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस पद की दौड़ में विधायक नैनार नागेन्द्रन काफी आगे हैं, लेकिन अभी उन्हें पार्टी में आये 10 वर्ष नहीं हुये हैं, जबकि पार्टी नियमों के अनुसार, इस पद के लिये यह भी एक शर्त है। जयललिता तथा पन्नौर सेल्वम सरकारों में मंत्री रह चुके नागेन्द्रन, इस समय विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता हैं।

इस दौड़ में कोयम्बटूर दक्षिण की विधायक वनन्ती श्रीनिवासन, जो एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं, भी शामिल हैं। वे इस समय भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा 2022 से पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी हैं। उनका नाम उस समय विशेष रूप से उभरकर सामने आया था, जब उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में जाने –माने अभिनेता कमल हासन को हराया था।

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी इस दौड़ में शामिल हैं। मुरुगन भी पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं था, यानी, अमेरिकी सरकार वित्तीय बाज़ार से ऋण जुटाने में असफल हो रही थी।

जैसा कि सर्वविदित है, दुनिया भर की सरकारें अपने बकाया ऋणों का भुगतान वास्तव में कभी नहीं करतीं, वे केवल नया ऋण लेकर पुराने ऋण का भुगतान करती हैं। इस फंड को इस गतिविधि के बिना सरकारें ठप पड़ जाँएँगी।

टैरिफ के कारण वित्तीय बाज़ारों में मची खलबली ने इस संभावना को जन्म दिया कि ट्रेज़री मार्केट पूरी तरह से ठप हो सकता है। इस संभावना को देखकर ट्रंप को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी टैरिफ योजना को स्थगित करने का आदेश दिया। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट की स्थिति ही कारण वह बनी, जिसने ट्रंप को पूरी तरह से अपने निर्णय को पलटने के लिए मजबूर किया।

दूसरी ओर, एक और बड़ा कारण यह था कि फोन की घंटियों की बाढ़ आ

गई थी- यानी व्यापारिक अधिकारियों और उद्योगपतियों के फोन कॉल्स की भरमार थी, जो इस नीति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे।

इन कॉल्स के जरिए अमेरिकी उद्योग और व्यापार जगत के नेता ट्रंप को इस नीति को आगे न बढ़ाने की सलाह दे रहे थे।

इनमें प्रमुख आवाज़ थी जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रमुख जैमी डिमोन की, जिन्होंने अपने वार्षिक पत्र में बैंक के शेयरधारकों को बहुत संयमित रूप में आगाह किया कि अमेरिका “नींद में चलते हुए मंदी की ओर बढ़ रहा है।”

ऐसे और भी कई लोगों ने इस संभावना की ओर इशारा किया था, जिनमें प्रमुख अर्थशास्त्री और पूर्व ट्रेज़री सचिव लैरी समर्स भी शामिल थे, जिन्होंने ट्रंप के आर्थिक पैकेज के बाद मंदी आने की भविष्यवाणी की थी।

“मंदी” शब्द अमेरिका के लिए डरावना है। इसका मतलब होता है- रोजगार और आय की हानि, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी और वित्तीय

बाज़ारों में उथल-पुथल। ये वही भयावह आर्थिक स्थितियाँ हैं, जो 1930 के दशक की महामंदी से जानी जाती हैं।

यहाँ तक कि ट्रंप के कुछ करीबी सहयोगी और समर्थक भी यह मानने लगे थे कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है, और एक बार यह शुरू हो गई तो कोई नहीं जानता कि यह कब और कहाँ जाकर रुकेगी।

इसके अलावा, कुछ शुरूआती परिणाम भी दिखने लगे थे। तेल की कीमतें गिर गई थीं और अमेरिका तेल का प्रमुख निर्यातक है। तेल और गैस उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। चीन को अमेरिका से तेल का निर्यात लगभग रुक चुका था, जिससे बाज़ार में अधिशेष (ग्लट) की स्थिति बन सकती थी।

कुल मिलाकर, डॉनल्ड ट्रंप की छवि को सीधा नुकसान हुआ है और वे अब अपनी हार के ज़ख्म सहला रहे हैं, हालांकि वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। घमंड का बुरा अंजाम।

इस बेमिसाल अवसर को हरगिज़ न गवाएं! जल्दी करें!

अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी एरीना कार पर जबर्दस्त ऑफ़र्स पाएं .

ALTO K10 ₹68 100* | **SWIFT ₹53 100*** | **WAGONR ₹68 100***

3 years | **100 000 km WARRANTY**** | EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

विशेष ऑफर

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at 1800-102-1800

T&C Apply Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 30th April, 2025.